www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 346 | जौनपुर, गुरुवार, 06 अगस्त 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

देवेश उत्तम होंगे इथियोपिया के नए राजदूत, जल्द संभालेंगे जिम्मेदारी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मंत्रालय के अनुसार, 2003 बैच के आईएफएस देवेश उत्तम जल्द अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। वर्तमान में वो बाल्टिक देश लिथुआनिया गणराज्य में भारत के एम्बेसडर हैं। देवेश, 2001 बैच के आईएफएस और इथियोपिया के वर्तमान राजदूत अनिल कुमार राय की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और इथियोपिया के संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक उन्नत किया गया। इथियोपिया ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से भी नवाजा, और दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए थे। देवेश उत्तम की बात करें तो, लिथुआनिया के दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार वो भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के रहने वाले हैं। उन्होंने 2003 में भारतीय विदेश सेवा में प्रवेश किया था। वे नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा (सीपीवी) विभाग के प्रमुख रह चुके हैं और प्रत्यर्पण मामलों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यालय के प्रभारी भी थे। विदेश में उनकी राजनयिक जिम्मेदारियों में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास में उप मिशन प्रमुख और न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन में काउंसलर के पद शामिल थे। न्यूयॉर्क में रहते हुए।

पीएम ई-ड्राइव से बैटरी लोकलाइजेशन तक, ईवी हब बनने की राह पर भारत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से परिवहन व्यवस्था का अहम हिस्सा बन रही है। ईवी बिक्री में 2016 के बाद करीब 46 गुना वृद्धि, घरेलू विनिर्माण के विस्तार, चार्जिंग नेटवर्क के विकास और सरकारी प्रोत्साहनों ने भारत को वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम में उभरती ताकत के रूप में स्थापित किया है। सरकार की एफएएमई, पीएम ई-ड्राइव, पीएलआई-ऑटो और पीएलआई-एसीसी जैसी योजनाएं मांग बढ़ाने के साथ-साथ बैटरी, वाहन और कंपोनेंट विनिर्माण के स्थानीयकरण पर जोर दे रही हैं। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार केवल प्रदूषण कम करने तक सीमित नहीं है। यह ऊर्जा सुरक्षा, पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटाने, रोजगार सृजन और कम-कार्बन विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शहरों में दैनिक आवागमन से लेकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी तक ईवी परिवहन के तौर-तरीकों को बदल रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यवस्थित नीतिगत समर्थन 2015 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान और एफएएमई इंडिया योजना के साथ मिला।

सुख-साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव करें सेवा - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिदिन की तरह आज गुरुवार को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषित साझा किया है। पीएम मोदी ने संस्कृत के श्लोक के माध्यम से लोगों से मातृभूमि की सेवा करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, "जिसमें सभी प्रकार की श्रेष्ठ वनस्पतियां और औषधियां पैदा होती हैं, वह पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित-पोषित, कल्याणकारी और सुख-साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करें।" इसके पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा था, "आत्मिक विकास व्यक्ति के भीतर सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की भावना का संचार करता है। इसी

से प्रेरित होकर आज हमारी युवा शक्ति देश को हर क्षेत्र में आगे ले जा रही है।" इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, "स्वयं का उत्थान करना और निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन की सच्ची नीति है। इसी ध्येय को आधार बनाकर गुणी और विद्वान लोग अपने ज्ञान, कौशल और प्रभाव का विस्तार करते हैं, ताकि वे समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें।" वहीं, मंगलवार को प्रधानमंत्री की ओर से एक्स पर लिखा गया था, "निरंतर प्रयास और साधना से हमारी प्रतिभा और निखरती है। आज हमारे युवा इन्हीं गुणों को आत्मसात कर दुनियाभर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं।" इसके साथ ही उन्होंने एक संस्कृत श्लोक, "न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति" साझा किया था। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। कर्मयोग या साधना के द्वारा जिसका अंतःकरण भली-भांति शुद्ध हो गया है, वह साधक समय आने पर उस परम ज्ञान को अपने आप ही अपने भीतर आत्मा में अनुभव कर लेता है।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बाढ़ प्रभावित अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे, राहत कार्यों की लेंगे जानकारी

अरुणाचल प्रदेश, (एजेंसी)। बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा कर रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। यह उनके तीन दिवसीय दौरे का आखिरी चरण है। इससे पहले वे असम और नागालैंड के बाढ़ और भूस्खलन वाले इलाकों का जायजा ले चुके हैं। जेपी नड्डा के कार्यक्रम में अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण शामिल है। वे राहत शिविरों में जाएंगे, टूटी सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को देखेंगे और आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी परेशानी सुनेंगे। उनका मकसद राहत, पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को मौके पर समझना है। कल बुधवार को जेपी नड्डा असम में थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा के साथ उन्होंने शिवसागर जिले के बिहुबोर और नेपाली खुटी इलाकों का दौरा किया था। यहां बाढ़ से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है, खेत पानी में डूब गए और मवेशियों का भी काफी नुकसान हुआ है। लोगों से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा था कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। राहत और पुनर्वास के काम में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया था कि केंद्र की टीम नुकसान का आकलन कर रही है ताकि मदद का काम जल्द शुरू किया जा सके। जेपी नड्डा ने असम के लोगों को भरोसा दिलाया कि पुनर्निर्माण में केंद्र हर संभव मदद करेगा। असम के बाद जेपी नड्डा नागालैंड पहुंचे। उनके साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आशोक सिंघल और राज्यसभा सदस्य फांगनोन कोन्याक भी थीं।

राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के लिए संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गुरुवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के लिए संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 'प्रादेशिक सेना' पर चर्चा केंद्रित रही। इस दौरान, रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 'विकसित भारत' के विजन को आगे बढ़ाने में प्रादेशिक सेना के योगदान को "महत्वपूर्ण" बताया। उन्होंने कहा कि रक्षा बलों की भूमिका मुख्य रूप से सुरक्षा संबंधी पहलुओं के इर्द-गिर्द घूमती है, वहीं प्रादेशिक सेना पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कार्यों जैसे अन्य क्षेत्रों में भी योगदान देती है। उन्होंने कहा,

"प्रादेशिक सेना 'नागरिक-सैनिक' अवधारणा का जीता-जागता उदाहरण है। इसके सदस्य असैन्य कार्यों में संलग्न रहते हुए भी, सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए वर्दी पहनते हैं। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि प्रादेशिक सेना प्रशिक्षित सैनिकों का एक आरक्षित भंडार बनाकर रक्षा बलों की क्षमता बढ़ाती है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र तैनात किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब कर्मी अपना कार्यकाल पूरा करके नागरिक जीवन में लौटते हैं, तो वे समाज और सेना के बीच एक जीवंत सेतु का काम करते हैं, जो लोगों, विशेषकर युवाओं को रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं।

यात्रियों को सुरक्षित पैकेज्ड पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रेलवे चला रहा 19 रेल नीर प्लांट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय रेलवे देशभर में 19 रेल नीर संयंत्र (प्लांट) संचालित कर रहा है, जो यात्रियों को सुरक्षित पैकेज्ड पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। प्रत्येक प्लांट प्रतिदिन 1 लाख बोतल पानी बनाने की क्षमता रखता है। यह जानकारी बुधवार को संसद में दी गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि महत्वपूर्ण ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर 'रेल नीर' की मांग वर्तमान में संचालित रेल नीर प्लांटों के जरिए पूरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत इसी क्षमता का एक नया रेल नीर प्लांट स्थापित करने की अनुमानित लागत करीब 10 करोड़ रुपए है। इसमें जमीन की लागत शामिल नहीं है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आई आरसीटीसी) को रेलवे नेटवर्क में मांग और

आवश्यकता के अनुसार चिन्हित स्थानों पर रेल नीर प्लांट स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। एक अन्य सवाल के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में आग जैसी संभावित दुर्घटनाओं से निपटने के लिए लगातार तैयारी, रोकथाम, त्वरित प्रतिक्रिया और राहत कार्यों पर काम कर रहा है। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र, फायर बकेट और रिले तथा इंटरलॉकिंग कक्षों में स्वचालित फायर अलार्म की व्यवस्था की गई है। रेलवे अपने अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए नियमित प्रशिक्षण भी देता है। स्टेशन प्रबंधक, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), कमर्शियल- कम-टिकट क्लर्क, लोको पायलट और सहायक लोको पायलट जैसे कर्मचारियों के प्रशिक्षण में अग्निशमन, प्राथमिक उपचार और आपदा प्रबंधन को शामिल किया गया है। रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे स्टेशनों पर कंट्रोल फोन उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से आग लगने की स्थिति में ओवरहेड इलेक्ट्रिक उपकरणों (ओएचई) की बिजली आपूर्ति तुरंत बंद की जा सकती है।

असम में बाढ़ पीड़ित छात्रों को राहत, मुफ्त किताबों के लिए सरकार देगी पैसे - सीएम सरमा

गुवाहाटी, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों को तेज कर दिया है। उन्होंने घोषणा की कि सभी प्रभावित जिलों में नई पाठ्यपुस्तकें भेज दी गई हैं और छात्रों को अध्ययन सामग्री खरीदने के लिए वित्तीय सहायता गुरुवार से शुरू की जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल 10 अगस्त को फिर से खुलने वाले हैं और यह सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं कि छात्र बिना किसी और बाधा के अपनी शिक्षा फिर से शुरू कर सकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि सभी प्रभावित जिलों में नई पाठ्यपुस्तकें पहले ही भेजी जा चुकी हैं, जबकि वर्दी रास्ते में है। अध्ययन सामग्री खरीदने

के लिए वित्तीय सहायता भी कल से शुरू की जाएगी और स्कूल 10 अगस्त को फिर से खुलेंगे – यह जानकारी मैंने आज अपने युवा मित्रों के साथ साझा की। मुख्यमंत्री ने बीमा कंपनियों से बाढ़ पीड़ितों द्वारा दायर दावों के निपटान में तेजी लाने की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन्हें बिना किसी अनावश्यक देरी के सहायता मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि बीमा कंपनियों को बाढ़ से संबंधित दावों का निपटान शीघ्रता और सहानुभूति के साथ करना चाहिए। उन्होंने उन लोगों को भी आश्वासन दिया जिनके पास बीमा कवरेज नहीं है कि राज्य सरकार आपदा से उबरने में उनकी हर संभव मदद करेगी। इस नागरिक समाज सदस्य जैसे बीमा रहित लोगों के लिए हमारी सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी। बाढ़ प्रभावित गांवों के अपने दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने निवासियों से बातचीत की, जिन्होंने हाल की बाढ़ के कारण हुए नुकसान और विस्थापन के अपने अनुभव साझा किए। बातचीत पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि उन्होंने प्रभावित परिवारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया है और समय पर पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है।

ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय साई का पुरवा में भाजपा जिला अध्यक्ष का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

अयोध्या (DKU live ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार

अयोध्या जनपद के दर्शन नगर साई का पुरवा गांव ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष राधेश्याम त्यागी जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिस अवसर पर बीके मुकेश भाई के माता-पिता के द्वारा तिलक टीका एवं पुष्प भेंट करके शुभकामना दिया गया। इस अवसर पर माउंट आबू ब्रह्माकुमारी हेडक्वार्टर से वरिष्ठ राज्य योगिनी उषा दीदी का भी जन्म दिवस मनाया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राधेश्याम त्यागी भाई पधारे हुए विशिष्ट पदाधिकारी द्वारा राज योगिनी उषा दीदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और वरिष्ठ राजयोगिनी उषा दीदी द्वारा राधेश्याम त्यागी भाई को भी ढेर सारी आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर पधारे हुए क्षेत्रीय संयोजक विदेश संपर्क विभाग रवी तिवारी जी एवीएन एमडी आरटी क्लब LIC रामकुमार गुप्ता.N Lal और प्रदीप सुशीलम भाई विवेकानंद केंद्र से भी मौजूद रहे किसान इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल दो ब्रिजेश पासवान जी भी मौजूद रहे।

कुछ साल पेट्रोल-डीजल की गाड़ियां खरीदने से बचें, ई20 नीति पर केजरीवाल ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरकार पहले ई20 पेट्रोल लागू कर चुकी है और अब आगे चलकर इसमें 50 फीसदी तक इथेनॉल मिलाने की तैयारी कर रही है।अरविंद केजरीवाल ने लिखा, प्केंद्र सरकार का क्या प्लान है? पता चल रहा है कि पेट्रोल में 50 प्रतिशत से ज्यादा की मिलावट करेंगे। अभी बस माहौल शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सरकार ने ई0 और ई10 वाली पुरानी गाड़ियों में जबरदस्ती ई20 पेट्रोल डलवाकर उन्हें कबाड़ा किया। अब जो लोग नई ई20 गाड़ी खरीद रहे हैं, उनके साथ भी यही होगा। आज अगर आप ई20 गाड़ी खरीदते हैं तो सरकार कुछ दिन बाद उसमें जबरदस्ती ई50 पेट्रोल डालकर उसका कबाड़ा कर देगी। केजरीवाल ने कहा कि सरकार जल्द ही डीजल में भी मिलावट करने वाली है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि अभी कुछ वर्ष आप पेट्रोल और डीजल की नई गाड़ियां खरीदने से बचें। केजरीवाल ने द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट को भी रीपोस्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में ई20 पेट्रोल लागू होने के बाद पुरानी पेट्रोल गाड़ियों का बाजार करीब 1,000 करोड़ रुपए तक गिर गया है। डीलरों का कहना है कि खरीदार अब डीजल गाड़ियों और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं।।

प्रेस क्लब में आयोजित 'प्रेस से मिलिए' कार्यक्रम में बोले डीएम,पंचकोसी परिक्रमा मार्ग समय से होगा तैयार

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार श्री वास्तव

अयोध्या।प्रेस क्लब सिविल लाइन अयोध्या में आयोजित 'प्रेस से मिलिए' कार्यक्रम में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने जिले की प्रमुख विकास परियोजनाओं, पर्यटन, यातायात और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनपद की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में चौदह कोसी एवं पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण शामिल है। पंचकोसी परिक्रमा से पहले इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना की लगातार निगरानी की जा रही है और अब केवल फिनिशिंग का कार्य शेष है।श्रद्धालुओं के अयोध्या में ठहराव को लेकर चलाई गई पर्यटन सुविधाओं हाटएयर बैलून, हेलीकाप्टर से अयोध्या भ्रमण तथा सरयू में क्रूज के बंद होने पर कहा कि सरयू में जलस्तर असामान्य रहता है।जिसके कारण वाटर मेटो व क्रूज के संचालन में दिक्कत आती है। यहां बांध के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट शासन स्तर पर लम्बित है। सिचाई विभाग द्वारा संचालित इस परियोजना की स्वीकृत के उपरान्त वाटर मेट्रो तथा क्रूज जैसी पर्यटन सुविधाओं संचालन ठीक प्रकार से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास के लिए सरकार लगातार बजट उपलब्ध करा रही है। मीडिया सेंटर के उपयोग के संबंध में पूछे गए सवाल पर जिलाधिकारी ने बताया कि उपनिदेशक सूचना को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही मीडिया सेंटर का प्रभावी उपयोग शुरू कराया जाएगा।सावन झूला मेले का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यह अपने आप में अनूठा और सामूहिक आस्था का उत्सव है। अयोध्या आने के बाद उन्हें इस परंपरा की विशेष जानकारी

मिली।उन्होंने कहा कि इस बार मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है।रामपथ पर पार्किंग और अव्यवस्थित वाहनों की समस्या पर उन्होंने बताया कि मार्ग पर दो-तीन स्थानों पर पार्किंग विकसित की जा रही है तथा अन्य उपयुक्त स्थलों का भी चयन किया जा रहा है।इससे जल्द ही यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में रिंग रोड का निर्माण अगले एक से डेढ़ वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है।एक प्रश्न के उत्तर में जिलाधिकारी ने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ किया गया कार्य हमेशा समाज के हित में होता है। उन्होंने अपने अब तक के प्रशासनिक कार्यकाल में किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव का सामना न करने की बात भी कही।कार्यक्रम का संचालन वीएन दास ने किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर जिलाधिकारी को वरिष्ठ पत्रकार जेपी तिवारी अध्यक्ष सुरेंद्र श्रीवास्तव व सचिव जेपी सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया तो प्रेस क्लब की ओर से रामलला का स्मति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में प्रेस क्लब के संरक्षण जेपी तिवारी, अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रीवास्तव, सचिव जेपी सिंह, पूर्व सचिव त्रियुग नारायण तिवारी,स्वरमिल चंद्रा राजेन्द्र प्रसाद पांडेय,राम कुमार सिंह स्थानीय संपादक जनमोर्चा, इंदु भूषण पांडेय,केबी शुक्ला,ओपी सिंह, सुरेंद्र सिंह,रवि पाठक,सहित बडी संख्या में प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों की मौजूदगी रही।

संपादकीय

डोपिंग का घुन

वाडा और एआईयू जैसी संस्थाओं की रिपोर्टों से भारत में इस समस्या के लगातार गहराने की पुष्टि हुई है, लेकिन खेल संस्थाओं या सरकार ने इस दिशा में कोई सख्त एवं प्रभावी पहल नहीं की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले ही दिन जुडो खिलाड़ी अरुण कुमार को डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण इस आयोजन से बाहर कर दिया गया। इसके पहले कई अन्य भारतीय खिलाड़ियों को भी इसी टेस्ट में फेल होने के कारण इन खेलों में भाग लेने से रोक दिया गया था। खेलों की दुनिया में भारत के लिए यह नई शर्मनाक स्थिति है। हालिया वर्षों से विश्व एंटी–डोपिंग एजेंसी– वाडा– की रिपोर्ट में भारत दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग, और कुश्ती में इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। दरअसल, कई एथलीटों के डोप टेस्ट में विफल होने के कारण ग्लासगो गेम्स में भारत के वेटलिफ्टिंग कोटा में कटौती कर दी गई। हाल में डोपिंग के मामले क्रिकेट, फुटबॉल और बॉक्सिंग जैसे खेलों में भी सामने आए हैं। नतीजतन, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट (एआईयू) ने भारत को उच्च–जोखिम वाली श्रेणी में डाल दिया है। एआईयू के इस निर्णय से खेल जगत में भारत की साख कमजोर हुई है। इसका नतीजा यह होगा कि अब अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय एथलीटों को अधिक सख्त और अतिरिक्त परीक्षणों से गुजरना होगा। बड़े खेल आयोजनों से पहले भारतीय खिलाड़ी डोप टेस्ट में फेल होते रहे, तो अंतरराष्ट्रीय खेल संघ भारत के कोटा (प्रतिनिधित्व के लिए खिलाड़ियों की संख्या) में कटौती कर सकते हैं। यह आशंका भी है कि अन्य देश और प्रायोजक भारतीय एथलीटों की उपलब्धियों को संदेह की नजर से देखने लगें। मगर इन अंदेशों से भारतीय खेल प्रशासक बेपरवाह नजर आते हैं। वाडा और एआईयू जैसी संस्थाओं की रिपोर्टों से देश में इस समस्या के लगातार गहराने की पुष्टि होती रही है, लेकिन खेल संस्थाओं या भारत सरकार ने इस दिशा में कोई सख्त एवं प्रभावी पहल नहीं की है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय भारत सरकार ने ओलिंपिक में अधिक मेडल जीतने की कथित योजनाओं और 2036 ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने जैसी महत्त्वाकांक्षी बातों में देशवासियों को उलझाए रखा है, उसी समय खेल की जड़ों को डोपिंग का घुन कुतरता जा रहा है।

370 पर बदजुबानी कर रहे थे जरदारी और शहबाज शरीफ, मोदी ने खुद आगे आकर दिया करारा जवाब

नीरज

जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान ने एक बार फिर पुराना राग अलापने की कोशिश की, लेकिन उसकी इस बदजुबानी का करारा जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक फैसला जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के लिए एक निर्णायक नए युग की शुरुआत था। उन्होंने दो टूक कहा कि बीते सात वर्षों में इन दोनों क्षेत्रों ने विकास, सुशासन और सामाजिक सशक्तिकरण के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया, जब पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने भारत के इस संवैधानिक फैसले को लेकर फिर से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच श्एक्सश पर अपने संदेश में कहा कि सात वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 और 35ए इतिहास बन गए थे और इसके साथ ही जम्मू–कश्मीर तथा लद्दाख के विकास का नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि वर्षों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहे महिलाओं, अनुसूचित वर्गों और अन्य वंचित समुदायों को अब भारतीय संविधान का पूरा संरक्षण और अधिकार मिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, उद्यमिता और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और केंद्र सरकार इन क्षेत्रों को विकसित भारत की यात्रा का मजबूत भागीदार बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस वर्ष अनुच्छेद 370 हटाए जाने की वर्षगांठ इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के वर्ष में पड़ रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए डॉ. मुखर्जी ने जिस संकल्प का सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को साकार हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस दिन को भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का स्वर्णिम दिवस बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर ने पिछले सात वर्षों में आतंकवाद से शांति, अलगाववाद से एकीकरण और अस्थिरता से विकास की ऐतिहासिक यात्रा तय की है। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने एक बार फिर 5 अगस्त को तथाकथित श्यौम–ए–इस्तेहसालश के रूप में मनाते हुए भारत के खिलाफ बयानबाजी की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दावा किया कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू–कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को अपना नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन जारी रखेगा तथा इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इसी सुर में बयान देते हुए कहा कि जम्मू–कश्मीर विवाद का समाधान पाकिस्तान की विदेश नीति का प्रमुख आधार बना रहेगा। उन्होंने भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की। वहीं उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी भारत के 5 अगस्त 2019 के फैसले को एकतरफा बताते हुए संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाने की मांग दोहराई। कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर वही पुराने आरोप लगाए, जिन्हें भारत लगातार खारिज करता रहा है। हालांकि पाकिस्तान की यह बयानबाजी इसलिए भी खोखली और दोगली नजर आती है क्योंकि जो देश कश्मीरियों के अधिकारों की दुहाई देता है, वही पाकिस्तान अधिकृत जम्मू–कश्मीर (पीओजेके) में अपने ही कब्जे वाले इलाके के लोगों पर दमनचक्र चला रहा है। हाल ही में खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पीओजेके में आंदोलन कर रहे स्थानीय लोगों को भारत की तरह पाकिस्तान का दुश्मन तक करार दिया। पीओजेके में असीम मुनीर के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिन्हें दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं, बिजली की आपूर्ति बाधित की गई, राशन और आवश्यक सुविधाओं पर भी असर पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी आवाज को बलपूर्वक कुचला जा रहा है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जो पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा, वह जम्मू–कश्मीर के लोगों की चिंता जताने का नैतिक अधिकार कैसे रखता है? स्पष्ट है कि कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की राजनीति महज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रचार और दुष्प्रचार तक सीमित रह गई है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू–कश्मीर में विकास परियोजनाओं को तेज गति मिली है। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जैसी वैश्विक पहचान मिली है।

डल झील में संगीत फव्वारे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी ने क्षेत्र में बढ़े विश्वास और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि की है। सड़क, रेल और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, शिक्षा और उद्यमिता के नए अवसर पैदा हुए हैं तथा स्थानीय हस्तशिल्प और पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिली है। पत्थरबाजी खत्म हो गयी है, अलगाववादी टूट चुके हैं और आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बहरहाल, सात वर्षों बाद तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक ओर पाकिस्तान है, जो अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही दमन, इंटरनेट बंदी, बिजली कटौती और सैन्य कार्रवाई के साये में जीने को मजबूर कर रहा है, जबकि दूसरी ओर भारत का मुकुट जम्मू–कश्मीर है, जो विकास, निवेश, पर्यटन, रोजगार और सुशासन की नई पहचान बना रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक निर्णय केवल एक संवैधानिक बदलाव नहीं था, बल्कि जम्मू–कश्मीर को अलगाववाद और पिछड़ेपन के दौर से निकालकर विकास और राष्ट्रीय एकीकरण की मुख्यधारा में लाने वाला निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यही वजह है कि आज पाकिस्तान के आरोपों से अधिक प्रभावशाली वह बदली हुई तस्वीर है, जिसे जम्मू–कश्मीर की धरती पर विकास, शांति और जनविश्वास के रूप में पूरी दुनिया देख रही है।

उन्नत बचपन की पहली शर्त- स्वस्थ भोजन, स्वस्थ भविष्य

ललित

विकसित भारत का स्वप्न केवल आधुनिक इमारतों, तेज अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक और विश्वस्तरीय आधारभूत संरचनाओं से पूरा नहीं होगा। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके बच्चे होते हैं। यदि बचपन स्वस्थ, संस्कारित, ऊर्जावान और मानसिक रूप से सुदृढ़ है, तो राष्ट्र का भविष्य स्वतः सुरक्षित हो जाता है। यदि बचपन ही

अस्वस्थ, मोटापे, मधुमेह, कुपोषण और गलत खान–पान की आदतों से घिर जाए, तो विकास की पूरी अवधारणा खोखली सिद्ध होने लगती है। इसलिए बच्चों का स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य मंत्रालय का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों और उनके आसपास जंक फूड की बिक्री, वितरण तथा प्रचार पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय इसी व्यापक दृष्टि का परिचायक है। यह केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व का गंभीर संदेश है। यह स्वीकार करने का साहसिक प्रयास है कि बच्चों की सेहत बाजार के मुनाफे से कहीं अधिक मूल्यवान है। यदि यह निर्णय प्रभावी ढंग से लागू होता है तो यह पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है। आज सबसे बड़ी चिंता यह नहीं है कि बच्चे भोजन कम खा रहे हैं, बल्कि यह है कि वे पोषण कम और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अधिक खा रहे हैं। रंग–बिरंगे पैकेट, आकर्षक विज्ञापन, कार्टून पात्रों की ब्रांडिंग, सोशल मीडिया का प्रभाव और हर गली–मोहल्ले में उपलब्ध फास्ट फूड ने बच्चों की स्वादेंद्रियों पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि घर का पौष्टिक भोजन उन्हें फीका लगने लगा है। यह परिवर्तन केवल खान–पान की आदत का बदलाव नहीं है, बल्कि धीरे–धीरे उनके शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार को भी प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिक शोध लगातार यह बताते रहे हैं कि अधिक वसा, अधिक नमक और अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थ बच्चों में मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, हार्मोन असंतुलन तथा मानसिक एकाग्रता में कमी जैसी अनेक समस्याओं का कारण बन रहे हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि जो बीमारियां पहले चालीस–पचास वर्ष की आयु में दिखाई देती थीं, वे अब किशोरावस्था और बचपन में ही दस्तक देने लगी हैं। यह केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि आने वाले समय में देश की उत्पादक क्षमता और मानव संसाधन पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला संकट है। बचपन की सबसे बड़ी आवश्यकता स्वाद नहीं, पोषण है। शरीर के विकास के साथ–साथ मस्तिष्क का तीव्र विकास भी बचपन में ही होता है। यदि इस अवस्था में बच्चों को संतुलित भोजन, ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, दालें, मोटे अनाज और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलें, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास कहीं अधिक प्रभावी होता है। इसके विपरीत जंक फूड क्षणिक स्वाद तो देता है, लेकिन शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं देता। परिणामस्वरूप बच्चा बाहर से स्वस्थ दिखाई देता है, किंतु भीतर से अनेक पोषण संबंधी कमियों का शिकार बनने लगता है। दुर्भाग्य यह है कि जंक फूड आज केवल भोजन नहीं रहा, बल्कि एक आक्रामक व्यावसायिक संस्कृति बन चुका है। विज्ञापनों के माध्यम से बच्चों के मन में यह धारणा बैठा दी गई है कि आधुनिकता का अर्थ पैकेटबंद भोजन है। लोकप्रिय खिलाड़ी, फिल्मी कलाकार और डिजिटल प्रभावक अनजाने में बच्चों को ऐसे उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं, जिनका अत्यधिक सेवन उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में केवल परिवारों को दोष देना उचित नहीं होगा। सरकार, उद्योग, विद्यालय, अभिभावक और समाज–सभी को अपनी–अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि जीवनशैली का निर्माण करने वाली प्रयोगशाला भी हैं। यदि स्कूल परिसर में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए, पोषण शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, विद्यालयों में रसोई बाग विकसित किए जाएं, बच्चों को स्वयं पौधे लगाने और प्राकृतिक भोजन के महत्व से जोड़ा जाए, तो यह परिवर्तन अधिक स्थायी होगा। केवल प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। स्वस्थ विकल्पों को स्वादिष्ट, आकर्षक और सुलभ बनाना भी उतना ही आवश्यक है। भारत की पारंपरिक भोजन संस्कृति विश्व की सबसे संतुलित और वैज्ञानिक भोजन प्रणालियों में मानी जाती है। बाजरा, ज्वार, रागी, दालें, छाछ, दही, अंकुरित अनाज, मौसमी फल, सब्जियां और घर का ताजा भोजन हमारे पूर्वजों की स्वस्थ जीवनशैली की पहचान रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आधुनिकता के नाम पर अपनी इस समृद्ध खाद्य संस्कृति को त्यागने के बजाय उसे नए स्वरूप में बच्चों तक पहुंचाएं। यदि विद्यालयों की कैंटीन में स्थानीय और पारंपरिक पौष्टिक व्यंजन उपलब्ध कराए जाएं, तो बच्चे धीरे–धीरे उसी स्वाद के अभ्यस्त हो सकते हैं। यह भी समझना होगा कि जंक फूड का प्रश्न केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अस्वस्थ बचपन का अर्थ है भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता खर्च, कार्यक्षमता में कमी, उत्पादकता का ह्रास और राष्ट्रीय आय पर प्रतिकूल प्रभाव। आज यदि बच्चों के पोषण पर निवेश किया जाता है तो वह आने वाले दशकों में स्वस्थ, सक्षम और नवाचारी नागरिकों के रूप में अनेक गुना लाभ देता है। इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य पर खर्च को व्यय नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे लाभकारी निवेश माना जाना चाहिए। अभिभावकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि घर में ही पैकेटबंद स्नैक्स, शीतल पेय और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ नियमित रूप से उपलब्ध होंगे, तो बच्चे उनसे दूर नहीं रह पाएंगे। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। यदि परिवार स्वयं संतुलित भोजन करेगा, साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा विकसित करेगा और बच्चों को रसोई से जोड़कर भोजन बनाने की प्रक्रिया में सहभागी बनाएगा, तो उनमें स्वस्थ भोजन के प्रति स्वाभाविक रुचि विकसित होगी। सरकारों को भी केवल स्कूलों तक सीमित न रहकर व्यापक नीति अपनानी होगी। बच्चों को लक्षित करने वाले भ्रामक खाद्य विज्ञापनों पर नियंत्रण, पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट चेतावनी, अत्यधिक चीनी और नमक वाले उत्पादों की पहचान को सरल बनाना, खेल मैदानों की संख्या बढ़ाना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण जागरूकता अभियान तथा स्थानीय स्तर पर सामुदायिक भागीदारी जैसे कदम समान रूप से आवश्यक हैं। यदि स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग मिलकर साझा रणनीति बनाएं तो परिणाम कहीं अधिक प्रभावी होंगे। आज समय की मांग है कि जंक फूड के विरुद्ध संघर्ष को केवल प्रतिबंध तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे स्वस्थ जीवनशैली के राष्ट्रीय अभियान का स्वरूप दिया जाए। जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता को जन–आंदोलन बनाया, उसी प्रकार स्वस्थ भोजन और पोषण को भी राष्ट्रीय जन–जागरण का विषय बनाया जाना चाहिए।

इतिहास में कौन प्रधानमंत्री ऐसे बदनाम हुआ

हरिशंकर व्यास

स्वतंत्र भारत के इतिहास में कौन प्रधानमंत्री ऐसे बदनाम हुआ? इतना खलनायक हुआ? कौन गालियों का ऐसा पात्र बना? और क्यों? इसका जवाब एक प्रौढ़ महिला ने सोमवार, 20 जुलाई 2026 को जंतर–मंतर पर दिया। मैंने उसे सोशल मीडिया पर सुना। उसने कहा, श्भारत ने बुरी सरकारें देखी हैं लेकिन ऐसी दुष्ट, क्रूर, नीच सरकार कभी नहींय! प्रौढ़ महिला हिंदू थी, पढ़ी–लिखी थी। और यह वाक्य सचमुच स्वतंत्र भारत के 14 प्रधानमंत्रियों के इतिहास में नरेंद्र मोदी के शासन की वह सच्चाई है, जो इतिहास में अमिट रहेगी। इस वाक्य को सुन मुझे भी अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के 12 प्रधानमंत्रियों के चेहरे याद हो आए। आप भी याद करें, पिछले 12 सालों में केवल प्रधानमंत्री मोदी के झूठों को, लोगों को बेवकूफ बनाने वाले जुमलों को, समाज को बांटने या दुनिया में भारत को श्कॉकरोचय बनाने वाली मूर्खताओं पर। और फिर बाकि प्रधानमंत्रियों पर। क्या ऐसा डा. मनमोहन सिंह, वाजपेयी से लेकर इंदिरा गांधी, नेहरू का कोई रिकॉर्ड है? मैंने 12 प्रधानमंत्रियों को पत्रकार के रूप में देखते, सुनते, समझते इनके हर समय के नैरेटिव का अनुभव लिया है। 1977 में दिल्ली के जंतर–मंतर के ही एक छोर पर कस्तूरबा गांधी मार्ग में हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग के बाहर खड़े हो कर मैंने इंदिरा गांधी के रायबरेली से हारने और राजनारायण के जीतने की खबर सुनी थी। जनता ने जोश भरे हुंकारे में अपनी जीत का तब जश्न मनाया था। बावजूद इसके इंदिरा गांधी को वैसी गालियां मिलती नहीं सुनीं जो इस सोमवार से जंतर–मंतर पर नौजवानों के उस सैलाब में सुनने को मिलीं है जो 35 वर्ष से नीचे की 60–65 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधि है! फिर भले लड़के हों या लड़कियां या महिलाएं! सन् 2011–12 में जंतर–मंतर पर ही मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ नौजवानों के नारे थे, पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोई झूठा, दलाल या देश बेचने वाला रंडवा, भगोड़ा आदि (वे शब्द, जिन्हें सुनना, बोलना, लिखना मेरे लिए असंभव है) नहीं कह रहा था। मैं सोशल मीडिया नहीं देखता हूं। पर कहते हैं भारत के घरों में सोशल मीडिया से मोदी को दी जा रही गालियों पर मजा लिया जा रहा है। जो नौजवान 2014 में मोदी को वोट देने के लिए मरा जा रहा था, जो मोदी को भगवान और विश्वगुरू करार दे रहा था, वही आज मोदी को ऐसे–ऐसे संबोधनों से चिन्हित कर रहा है, जो संभवतया दुनिया के किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को शायद ही कभी मिले हों। हां, वैश्विक पैमाने पर भी सोचें। दुनिया में उन नेताओं को बहुत गालियां मिली हैं, जिन्होंने नरसंहार, तानाशाही का पशुपन दिखाया। पर स्टालिन, हिटलर, माओ से लेकर पोल पोट, ईदी अमीन, चिली के पिनोशे, अफगानिस्तान के मुल्ला उमर या हाल में तख्तापलट वाली बांग्लादेश की हसीना वाजिद, नेपाल के केपी शर्मा ओली आदि सभी की गालियों की दास्तां उनकी विचारधारा केंद्रित क्रूरता, नरसंहार, सत्ता की भेड़िया भूख, धर्मांधता जैसे कारणों से है। वह पूरी सत्ता या सिस्टम या सरकार के खिलाफ था। जबकि नरेंद्र मोदी का मामला अनूठा है। हिंदुओं की व्यक्तिगत भक्ति का कल्कि अवतार अब हिंदू लड़के–लड़कियों में ही उस ठग के रूप में है, जिस पर जंतर–मंतर के यूथ उबाल में यह पछतावा करता हुआ है कि हां, मैंने भी अपने मां–बाप के साथ मोदी को वोट दिया था। लेकिन मुझे घरवालों ने ही कहा– जाओ दिल्ली, जंतर–मंतर! और जंतर–मंतर पर पुलिस–सुरक्षा बलों की पूरी फौज नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह के लिए युवाओं से गालियां निकलवाते हुए है। नौजवान उस रचनात्मकता, बेलौस अंदाज में तख्तियों, मीम, पोस्टर, मोदी के फोटो के साथ जूते लटकाए हुए डायलॉग मार रहे हैं, जिसकी कल तक कल्पना नहीं थी। यह नोट रखें कि नौजवानों के लिए न तो सोनम वांगचुक का अर्थ है और न कथित कॉकरोच पार्टी के चेहरों या पदाधिकारियों का। नई पीढ़ी अनुभवों के गुस्से में, अपनी दशा, अपने साथ झूठ, धोखे, फरेब–ठगी से घायल है। सभी केवल और केवल मोदी पर केंद्रीत है। ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इमरजेंसी से पहले और बाद में इंदिरा गांधी को गालियां मिलीं थी, पर उसमें राजनीति, गैर–कांग्रेसवाद, विचार, अनुभव सब थे। श्गली–गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर हैय जैसे नारे जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने बच्चों को बिल्ले बांटते हुए बताए थे। अब बच्चे खुद ही गढ़ रहे हैं। सभी के निशाने में केवल एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं। बच्चे, लड़के–लड़कियां, युवा के दिल–दिमाग में मोदी एकमेव हैं। अमित शाह और चुनाव आयोग के लिए संभव है कि वे जंतर–मंतर के कॉकरोचों की भीड़ से फोटो स्कैन कर इन सभी के नाम वोटर लिस्ट से काट दें। मतलब मोदी–शाह गालियों के बावजूद यूपी आदि के चुनाव जीतते जाएं। लेकिन अब वह जैविक नौजवान जोश कभी नहीं लौटेगा, जिसने कभी कभी घर–घर हर–हर मोदी बनाया था।

नक्सल–मुक्त भारत–एकीकृत रणनीतियों से वामपंथी उग्रवाद पर निर्णायक विजय

भारत ने वामपंथी उग्रवाद से लगभग पूरी तरह मुक्त होने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब देश का कोई भी जिला वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित नहीं है। यह परिवर्तन एक बहुआयामी और समन्वित रणनीति का परिणाम है, जिसमें सुरक्षा अभियान, बुनियादी ढांचे का विस्तार, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का पुनर्वास, आदिवासी कल्याण और सुशासन को समान शांति व सुरक्षा के नए युग का शुभारंभ लगभग छह दशकों तक भारत वामपंथी उग्रवाद की चुनौती से जूझता रहा। यह केवल एक सुरक्षा समस्या नहीं थी, बल्कि लाखों आदिवासी परिवारों और उन गांवों के लिए रोजमर्रा की कठोर वास्तविकता थी, जो लंबे समय तक सड़कों, स्कूलों व समावेशी विकास के अवसरों से वंचित रहे। लगातार होने वाली हिंसा ने इन क्षेत्रों में जीवन को अनिश्चितता और भय से घेर रखा था। 31 मार्च 2026 को इस स्थिति में एक ऐतिहासिक बदलाव आया और भारत की आंतरिक सुरक्षा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल हुआ। देश ने नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता प्राप्त की। मई 2014 में केंद्र सरकार के सत्ता में आने के समय रेड कॉरिडोर देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने मौजूद सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक था। पहले अपनाए गए उपाय काफी हद तक बिखरे हुए और घटनाओं पर आधारित थे। इनमें अक्सर समस्या की मूल वजहों को दूर करने के बजाय उसके तत्काल प्रभावों से निपटने पर अधिक जोर दिया जाता था। इसके बाद वामपंथी उग्रवाद की चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा, विकास, बुनियादी ढांचे, सुशासन और जनकल्याण को एक साथ जोड़ने वाली व्यापक एवं एकीकृत रणनीति अपनाई गई। इसी समन्वित दृष्टिकोण ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी बदलाव की नींव रखी। पिछले बारह वर्षों में यह बदलाव तीन परस्पर जुड़े और एक–दूसरे को मजबूत करने वाले प्रयासों के माध्यम से आया। लोगों का विश्वास और भरोसा बहाल करने के लिए सुरक्षा अभियानों को सुदृढ़ किया गया, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास के लिए व्यवस्थित तंत्र विकसित किए गए तथा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तक लगातार पहुंच बनाई गई। बुनियादी ढांचे के विस्तार के तहत भौतिक व डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया, दूर–दराज के क्षेत्रों तक प्रशासन की पहुंच बढ़ाई गई और दीर्घकालिक आर्थिक अवसरों का सृजन किया गया। वहीं, कल्याणकारी गतिविधियों में सम्मान, समावेशी सेवाओं की पहुंच, सांस्कृतिक समावेशन और प्रभावित समुदायों को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। इनमें से प्रत्येक प्रयास ने दूसरे प्रयासों को और मजबूत किया। सुरक्षा ने विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया, विकास ने लोगों का विश्वास गहरा किया और विश्वास ने कल्याणकारी पहलों को गति प्रदान की। यह कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं थी, जिसमें एक कदम के बाद दूसरा कदम उठाया गया होय बल्कि यह शांति, विकास एवं विश्वास को लगातार मजबूत करने वाली एक सशक्त और अविच्छिन्न कड़ी थी। सरकार पर भरोसा बहाल करना इस प्रयास का उद्देश्य संवेदनशील और दूर–दराज के क्षेत्रों में सरकार की निरंतर उपस्थिति के माध्यम से लोगों का विश्वास और भरोसा बहाल करना था। प्रभावी व समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों तथा सरकारी संस्थाओं के बीच तालमेल को और मजबूत किया गया। इस समग्र दृष्टिकोण ने स्थानीय समुदायों और सरकारी तंत्र के बीच लंबे समय से बनी दूरी को कम करने तथा आपसी विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी विद्रोह से हुई। यह आंदोलन माओवादी विचारधारा और सशस्त्र क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था। इसका मूल विचार हिंसक क्रांति के माध्यम से सत्ता हासिल करना था। समय के साथ वामपंथी उग्रवाद का विस्तार कई क्षेत्रों में हुआ। उग्रवादी संगठनों ने हथियारों और संसाधनों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों तथा पुलिस शस्त्रागारों को भी निशाना बनाया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, नक्सलियों के लगभग 92 प्रतिशत हथियार पुलिस शस्त्रागारों से लूटे गए थे। वर्ष 2004 में कई उग्रवादी संगठनों के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) में विलय के बाद यह संगठन और अधिक संगठित एवं प्रभावशाली हुआ। इसके परिणामस्वरूप वामपंथी उग्रवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। साल 2004 से 2014 का दशक वामपंथी उग्रवाद के इतिहास में सबसे हिंसक दशकों में से एक था। हिंसा 2010 में अपने चरम पर थी, जब एक ही साल में 1,936 घटनाएं हुईं और 720 नागरिकों की मौत हुई। पूरे दशक में हिंसा की 17,542 घटनाएं हुईं, जिनमें सुरक्षा बलों के 1,913 जवान और 5,019 नागरिक मारे गए। कोई एक जैसी राष्ट्रीय नीति नहीं थी। राज्य सरकारें अलग–अलग काम करती थीं। फिर भी, 2009 में सरकार ने सार्वजनिक रूप से माना कि नक्सलवाद भारत के सामने सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती है, जिसका दायरा कश्मीर और पूर्वोत्तर से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को मंजूरी मिलने के साथ वर्ष 2015 में एक निर्णायक कदम उठाया गया। इसके तहत पहले अपनाए जाने वाले कामचलाऊ और बिखरे हुए दृष्टिकोण की जगह एक व्यवस्थित, समन्वित और संपूर्ण सरकारी तंत्र को शामिल करने वाली रणनीति अपनाई गई। इस रणनीति के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती, विशेष प्रशिक्षण और सुरक्षा अभियानों को मजबूत करने के साथ–साथ वामपंथी उग्रवाद के सामाजिक–आर्थिक कारणों पर भी ध्यान दिया गया। इसके लिए सुरक्षा संबंधी व्यय, विशेष बुनियादी ढांचा योजना और विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) जैसी योजनाओं के माध्यम से आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए। 2017 में विशेष केंद्रीय सहायता योजना की शुरुआत के बाद से अब तक लगभग 4,289.20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इन गतिविधियों ने सुरक्षा उपायों के साथ–साथ विकास और जनकल्याण को गति देकर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी बदलाव की नींव मजबूत की। विशेष बुनियादी ढांचा योजना (एसआईएस) के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष बलों, विशेष खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस ढांचे को मजबूत करने तथा सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण के लिए 1,761 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। वर्ष 2014द्15 से अब तक सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत 3,805.04 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षा बलों की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं व प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करना, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के पुनर्वास में सहायता करना तथा शहीद सुरक्षा कर्मियों और हिंसा में मारे गए नागरिकों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करना है। पहली बार, भारत ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बातचीत, सुरक्षा और समन्वय पर आधारित एक व्यवस्थित और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। गृह मंत्रालय के तहत अधिक केंद्रीकृत एवं समन्वित ढांचे के माध्यम से सरकारी प्रयासों को आगे बढ़ाया गया, जिससे नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और प्रभावित क्षेत्रों में कार्रवाई की गति को मजबूत किया जा सका।

कौशल, इंटर्नशिप से विधि विद्यार्थियों के लिए करियर की संभावनाएं – प्रो. प्रदीप कुमार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान में बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) प्रथम सेमेस्टर के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए आयोजित तीन दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम का समापन गुरुवार को हुआ। कार्यक्रम के अंतिम दिवस विद्यार्थियों को विधि शिक्षा में करियर की संभावनाओं, व्यक्तित्व विकास तथा मानसिक स्वास्थ्य के महत्व से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल के समन्वयक प्रो. प्रदीप कुमार ने ष्बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) के पश्चात करियर एवं रोजगार की संभावनाएंष विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि विधि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायपालिका, प्रशासन, कॉर्पोरेट क्षेत्र और समाज सेवा में नेतृत्व स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों से अध्ययन के साथ–साथ इंटर्नशिप, मूट कोर्ट, विधिक शोध, ड्राफ्टिंग तथा प्रभावी संचार कौशल विकसित करने का आह्वान किया, जिससे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और करियर के बेहतर अवसर प्राप्त किए जा सकें। उन्होंने न्यायिक सेवा, अधिवक्ता के रूप में वकालत, लोक अभियोजक, सरकारी विधि अधिकारी, कॉर्पोरेट लॉ, बैंक एवं सार्वजनिक उपक्रमों में विधि अधिकारी, राष्ट्रीय एवं राज्य आयोगों, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं, विधिक शोध एवं शिक्षण, लीगल कंसल्टेंसी, आर्बिट्रेशन एवं मेडिएशन, कंपनी सेक्रेटरी, भारतीय सेना की जेएजी (जज एडवोकेट जनरल) शाखा तथा भारत और विदेश की प्रतिष्ठित लॉ फर्मों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध करियर के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधि के क्षेत्र में निरंतर सीखने की प्रवृत्ति, व्यावहारिक अनुभव और कौशल विकास सफलता की कुंजी हैं। द्वितीय सत्र में विश्वविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में हैप्पीनेस एवं मेडिटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग, ध्यान एवं प्रेरक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को मानसिक एकाग्रता, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास तथा स्वस्थ जीवनशैली का महत्व बताया गया। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की। तीन दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम का उद्देश्य नवप्रवेशी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, उपलब्ध संसाधनों, करियर की संभावनाओं तथा व्यक्तित्व विकास से परिचित कराना था। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सकारात्मक दृष्टिकोण एवं व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में संस्थान के विभागाध्यक्ष एवं निदेशक प्रो. विनोद कुमार, डॉ. अनुराग मिश्र, डॉ. प्रियंका कुमारी, डॉ. वनिता सिंह, जय सिंह, विकास सिंह सहित संस्थान के समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

9 अगस्त को जौनपुर में होगी चतुर्थ जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता, 300 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। योगासन स्पोर्ट्स एलायंस एसोसिएशन के तत्वावधान तथा मीरा वेलफेयर फाउंडेशन, जौनपुर के सहयोग से चतुर्थ जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन 9 अगस्त को मोहम्मद हसन पी.जी. कॉलेज, जौनपुर में किया जाएगा। प्रतियोगिता में जनपद के लगभग 70 विद्यालयों के 300 से अधिक खिलाड़ी अपनी योग प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसकी जानकारी बुधवार को ऋषि योगा संस्थान, गोसाई मंदिर में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था की अध्यक्ष एवं योग प्रशिक्षक रजनी साहू ने दी। उन्होंने कहा कि योगासन अब केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उभरता हुआ प्रतिस्पर्धात्मक खेल बन चुका है। प्रतियोगिता का उद्देश्य जनपद की प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराना तथा उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। रजनी साहू ने कहा कि वर्तमान भागदौड़ भरी जीवनशैली में योग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का सबसे प्रभावी

माध्यम है। योग के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास, एकाग्रता और सकारात्मक सोच का विकास होता है, जिससे विद्यालयों में इसके प्रति लगातार रुचि बढ़ रही है।

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 8 से 25 वर्ष आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाएं विभिन्न वर्गों में प्रतिभाग करेंगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार, मेडल तथा प्रमाण–पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही चयनित खिलाड़ियों को आगामी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने जनपद के विद्यालयों, अभिभावकों, खेल प्रशिक्षकों और सामाजिक संगठनों से अधिक से अधिक बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे जौनपुर की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योग एवं खेल संस्कृति के प्रचार–प्रसार में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर संस्था की महासचिव डॉली गुप्ता, सचिव मधु गुप्ता, इंदिरा जायसवाल, कोषाध्यक्ष रचित साहू, सहकार भारती जौनपुर के अध्यक्ष कुँवर प्रदीप सिंह रिंकू, रामजी साहू, तनुष्का साहू सहित संस्था के अन्य पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

14 अगस्त तक कराएं फसल बीमा, धान पर दो प्रतिशत लगेगा प्रीमियम

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उप कृषि निदेशक ने बताया कि खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। उप कृषि निदेशक डा0 अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि गैर–ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 तथा ऋणी (केसीसी धारक) किसानों के लिए 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। बीमा के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी और स्वयं बुवाई प्रमाण–पत्र आवश्यक होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के अधिसूचित फसलों (धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, अरहर, तिल) पर कुल बीमित राशि का मात्र दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। वही मौसम आधारित योजना में केला, टमाटर और मिर्च को शामिल किया गया है। किसान कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों, सहज जन सेवा केन्द्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर बीमा करा सकते है। दैवीय आपदा की स्थिति में फसल नुकसान होने पर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क किया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 गंगाराम गौतम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का किया औचक निरीक्षण दिया आवश्यक निर्देश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 गंगाराम गौतम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरसठी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भन्नौर एवं जयगोपालगंज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित पाए गए। चिकित्सालयों में आवश्यक औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पाई गईं तथा व्यवस्थाएँ संतोषजनक रहीं। निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समय से उपस्थित रहकर आने वाले प्रत्येक मरीज को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराएँ। वर्तमान में वायरल फीवर के बढ़ते मामलों को दृष्टिगत रखते हुए अधिक से

अधिक आवश्यक जाँच कराने, रोगियों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने तथा उन्हें वायरल संक्रमण से बचाव के उपायों के संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, एआरवी और एएसवी की उपलब्धता पर्याप्त पाई गई। चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि भविष्य में भी इनकी निर्बाध एवं सतत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

अखिल की पुस्तकों का विनोद कुमार सिह डी जी पी सी आई डी ने किया हुआ लोकार्पण -अखिलेश निगम

लखनऊ – समावेशी साहित्य संस्थान के तत्वाधान में प्रख्यात साहित्यकार एवं पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश निगमश्अखिलश्की दो पुस्तकों का भव्य लोकार्पण उ०प्र०हिन्दी संस्थान के निराला सभागार में श्री गणेश पूजन के बाद मंच पर अतिथियों का अग वस्त्र एवं मोती की माला तथा माल्या अर्पण के बाद सम्पन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में अखिलेश निगम के कहानी संग्रहश्अपने–अपने तर्कश (प्रभात प्रकाशन)तथा समीक्षाश्ग्रन्थ अखिलश्का साहित्यःमनन एवं मूल्यांकनश का लोकार्पण हुआ एवं परिचर्चा कार्यकम हुआ। साथ ही समावेशी साहित्य संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया तथा संस्था के शुभंकर को भी लोकार्पित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विनोद कुमार सिंह,पुलिस महानिदेशक,सी०आई०डी० ने अखिलेश निगम के विभागीय कार्यों के साथ–साथ साहित्य सृजन की विलक्षण क्षमता की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि विभागीय व्यस्तता के बीच साहित्य लेखन के लिए समय निकालना बहुत कठिन है।विशिष्ट अतिथि के रूप में आशुतोष कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, सी०आई०डी०ने अखिल के व्यक्तित्व और साहित्य दोनों की प्रशन्शा करते हुए कहा कि अखिलेश निगम का व्यक्तित्व अत्यन्त सरल, सहज एवं अहंकार शून्य है। उसी प्रकार इनका साहित्य भी पाठकों के लिए सरल, सहज एवं रोचक है। उड़ीसा से पधारे उमेश कुमार प्रजापतिश्अलखश्ने नवगठित समावेशी साहित्य संस्थान की स्थापना के लक्ष्य के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी तथा प्रा० योगेन्द्र प्रताप सिंह,डॉ० दिनेश अवस्थी,डॉ०अमिता दूबे,तरूण प्रकाश ने लोकर्पित होने वाली पुस्तकों की सारगर्भित समीक्षा की। उपरोक्त अवसर पर सीआईडी विभाग के आईजी अखिलेश निगम का केक काटकर जन्मदिन आयोजन में हर्षो उल्लास के साथ मनाया गया उपरोक्त अवसर पर श्री निगम ने कहा जन्मदिन केक काटने के पूर्व दीप जलाकर मानना चाहिए उपरोक्त अवसर पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद्र कुशवाहा ने माला पहनकर निगम जी को जन्मदिन की बधाई दी वहीं पर हिंदी संस्थान की प्रबंधिका डॉ अमित दुबे ने श्री निगम को अंग वस्त्र एवं मालया अर्पण कर हिंदी संस्थान में आयोजन पर एवं उनके जन्म दिवस पर श्री निगम को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रो०हरिशंकर मिश्र जी ने अखिल के साहित्य के प्रत्येक विधा में किए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद कुमार प्रमोद ने मंच को सजाकर एवं जनमानस को काव्य पाठ करते–करते हंसते–हंसते लोटपोट करते हुए किया

मिलेट्स खाए और बीमारियों को दूर भगाएं

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। कृषि विभाग द्वारा गुरुवार को विकास खण्ड केराकत एवं डोभी स्थित बी0आर0सी0 सभागार में उत्तर प्रदेश मीलेट्स पुनरोद्धार योजना अन्तर्गत स्कूल अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें श्री अन्न के महत्व एवं उपयोगिता से अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षक उप परियोजना निदेशक आत्मा डा. रमेश चंद्र यादव ने अध्यापकों को अवगत कराया कि कुपोषण आज देश की बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है इससे बचने का सबसे सरल तरीका है मिलेट्स का सेवन, सरल शब्दों में कहें तो गेहूं और चावल को छोड़कर ज्वार, बाजरा, मक्का, सावा, कोदो, रागी, जौ, जई आदि को मोटे अनाज में शुमार किया जाता है। गेहूं और चावल की तुलना में मोटे अनाजों की सतह तुलनात्मक रूप से खुरदरी होती है। आहार व पोषण विशेषज्ञ मोटे अनाजों की खूबियों से इतने प्रभावित हैं कि इन्हें सुपरफूड्स के रूप में मान्यता दे रहे, अध्यापक अपने विद्यालय के छात्रछात्राओ को मोटे अनाजो (श्री अन्न) की उपयोगिता से जागरूक करें ताकि उनके परिजन मोटे अनाज की खेती करें, श्री अन्न को एमडीएम में भी शामिल किया जाएगा, जिससे जनपद में मीलेट्स के उत्पादन को बल मिलेगा और मानव स्वास्थ्य वेहतर होगा तथा किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों की उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने श्री अन्न योजना का नाम दिया है दूसरे अनाजों की तरह ही मोटे अनाज चीला, खीर, खिचड़ी, दलिया, कटलेट, सूप, उपमा, डोसा, इडली, बिस्कुट, स्नेक्स, चिक्की आदि रूपो में खाया जा सकता हैं, उन्होंने ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च (आईआईएमआर) हैदराबाद के अनुसार मोटे अनाज सिलिएक डिजीज के इलाज में लाभ प्रद है। इसका कारण है मोटे अनाज ग्लूटेन फ्री है। गेहूं में ग्लूटेन नामक तत्व पाया जाता है जिससे कुछ लोगों में सीलिएक बीमारी रोग हो जाता है। विशेषज्ञ मोटे अनाज को मधुमेह और कैंसर रोकने वाले तत्वों से भरपूर मानते हैं, पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में होने के कारण मोटे अनाज को एनीमिया व कुपोषण की समस्या को दूर करने में सहायक माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के अनुसार मोटे अनाज वात एवं कफ दोष को संतुलित करने में सहायक है। मोटे अनाजों में फाइबर की प्रचुरता उन्हें मधुमेह और मोटापे से बचाती है मोटे अनाजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है तभी मधुमेह व हृदय रोगियों को खाने की सलाह दी जाती है। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक अशोक पाल ने मिलेट्स प्रसंस्करण की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक संजय कुमार गुप्ता तथा संचालन एडीओ एजी. दयानन्द सिंह ने किया। इस मौके पर बेसिक शिक्षा विभाग के 50 शिक्षक एवं शिक्षिकाएं से मौजूद रहें।

लगातार बारिश के चलते जौनपुर के सभी परिषदीय विद्यालयों में आज अवकाश घोषित – जिलाधिकारी

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जनपद में बुधवार रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. के निर्देश पर गुरुवार को जिले के सभी परिषदीय (बेसिक) विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने अवकाश संबंधी सूचना तत्काल सभी शिक्षक समूहों एवं संबंधित विद्यालयों को भेज दी है, ताकि समय रहते सभी को इसकी जानकारी मिल सके। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में जनपद के सभी सरकारी परिषदीय विद्यालयों में गुरुवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसकी सूचना सभी प्रधानाध्यापकों और संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि लगातार हो रही

बारिश और खराब मौसम को देखते हुए बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें तथा उन्हें विद्यालय भेजने से बचें। मौसम सामान्य होने तक सतर्कता बरतना आवश्यक है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह भी बताया कि यह आदेश केवल परिषदीय (सरकारी) विद्यालयों पर लागू है। जनपद के गैर–मान्यता प्राप्त एवं निजी विद्यालय अपने स्तर पर संचालित हो रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने और मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है।

यूपी में तेज बारिश से नदियों में बाढ़ का खतरा फिर गहराया, कई जिलों में कटान तेज

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश में सोमवार रात से ही जारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ और कटान का खतरा फिर से बढ़ गया है। बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के कारण घाघरा, गंगा, शारदा और सरयू नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है और राहत व बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है। जलभराव के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं वज्रपात से मीरजापुर व सोनभद्र में एक–एक लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और गरज–चमक के साथ बौछारों की संभावना जताई है। गोंडा में 52 मिमी बारिश के बाद घाघरा नदी के किनारे नवाबगंज के दत्तनगर स्थित बाणीमाझा में 24 घंटे के भीतर करीब 100 बीघा कृषि भूमि नदी में समा गई। एल्गिन ब्रिज पर घाघरा खतरे के निशान से नौ सेंटीमीटर नीचे और अयोध्या में सरयू 37 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। घाघरा में 2.63 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। डीएम प्रियंका निरंजन ने अधिकारियों को राहत कार्यों के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज से 62 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद शारदा नदी खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। सीतापुर में बैराजों से 3.26 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद करीब 130 गांवों पर बाढ़ और कटान का खतरा बना हुआ है। बहराइच में एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी खतरे के निशान से मात्र छह सेंटीमीटर नीचे पहुंच गई है। गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। फर्रुखाबाद में 50 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, 40 गांवों के संपर्क मार्ग डूब गए हैं और खेतों में नाव चल रही हैं। कानपुर में बिठूर का ब्रह्मावर्त घाट जलमग्न हो गया है, जबकि कन्नौज और उन्नाव में भी गंगा चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 14 सेंटीमीटर बढ़ा है,।

यूपी में शिवालयों और यात्रा रूटों पर बिजली व्यवस्था होगी चाक-चौबंद

लखनऊ, (संवाददाता)। दिन रात चलने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार ने श्रावण मास के धार्मिक आयोजनों एवं वर्षा ऋतु के दौरान विद्युत सुरक्षा और निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर डिस्काम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं एवं आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्तर पर विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा है। मंगलवार को शक्ति भवन से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी डिस्काम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रबंध निदेशक ने कहा कि मंदिरों, शिवालयों, कांवड़ मार्गों, मेलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों के आसपास स्थित विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों एवं अन्य विद्युत उपकरणों का विशेष निरीक्षण कर तत्काल मरम्मत कर लें। किसी स्थान पर खुले तार, झुके हुए विद्युत पोल अथवा अन्य संभावित जोखिमों को तत्काल दूर किया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला प्रशासन, पुलिस एवं आयोजन समितियों के साथ समन्वय बनाकर विद्युत व्यवस्था की सतत निगरानी करें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नियमित संवाद स्थापित कर उन्हें अपने क्षेत्रों में चल रहे अनुरक्षण कार्यों एवं विद्युत व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध कराएं। बिना सुरक्षा उपकरणों के किसी भी कर्मचारी से कार्य न कराया जाए। सुरक्षा नियमों की अनदेखी से होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

बड़ौदा यूपी बैंक के सेवानिवृत्त मैनेजर की सड़क हादसे में मौत पर 39 लाख रुपये मुआवजे का आदेश'

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले बड़ौदा यूपी बैंक के सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक के परिजनों को बड़ी राहत देते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को ब्याज सहित 39 लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह राशि आदेश की तिथि से दो माह के भीतर मृतक के आश्रितों को उपलब्ध कराई जाए। मामले के अनुसार, लाइन बाजार थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी, मुरादगंज निवासी पन्नालाल (64 वर्ष), जो बड़ौदा यूपी बैंक से सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक थे, 3 जुलाई 2023 की रात करीब 8रू30 बजे स्कूटी से जा रहे थे। इसी दौरान पॉलिटेक्निक चौराहे के निकट एक तेज रफ्तार एवं लापरवाही से चलाई जा रही मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद मृतक की पत्नी शांति एवं उनके पुत्रों ने मोटरसाइकिल चालक, वाहन स्वामी तथा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में क्षतिपूर्ति याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों का परीक्षण कराया तथा आवश्यक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मृतक की मासिक पेंशन 41,891 रुपये स्वीकार की। दोनों पक्षों की दलीलों, अभिलेखों एवं गवाहों के बयानों का गहन परीक्षण करने के बाद अधिकरण ने स्पष्ट रूप से माना कि दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक की उपेक्षा एवं लापरवाही के कारण हुई थी। इसके आधार पर न्यायालय ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह मृतक के आश्रितों को ब्याज सहित 39 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति निर्धारित अवधि के भीतर अदा करे।

प्रयागराज अदालत का सांसद पप्पू यादव को तलब करने का आदेश

लखनऊ, (संवाददाता)। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज की अदालत ने साधु–संतों के वेश में कथित रूप से चंदा चोरी का प्रदर्शन करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपों से जुड़े मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कक्ष संख्या–10) योगेश जैन की अदालत ने प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ मानते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पप्पू यादव को 11 अगस्त 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है।यह मामला भाजपा के विधि विभाग के प्रदेश सह–संयोजक एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा द्वारा दायर परिवाद पर आधारित है। शिकायतकर्ता ने अदालत में आरोप लगाया कि संसद भवन के सामने साधु का वेश धारण कर ।

यूपी में 15613 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे स्थानांतरित, 15 अगस्त तक परिषदीय स्कूलों में किए जाएंगे शिफ्ट

लखनऊ, (संवाददाता)। सरकारी स्कूलों के पास संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय परिसर में स्थानांतरित करने का अभियान तेज कर दिया गया है। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की दूरी निकटतम प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय (जहां कक्षा–1 संचालित है) से 200 मीटर तक है और जो गैर विभागीय भवनों में चल रहे हैं। उन्हें 15 अगस्त तक संबंधित विद्यालय परिसर में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की निदेशक हर्षिता माथुर व स्कूल शिक्षा विभाग की महानिदेशक मोनिका रानी ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों

और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को संयुक्त निर्देश जारी किए हैं। दोनों विभागों की ओर से पहले 24 जून को विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत 1,89,208 आंगनबाड़ी केंद्रों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 1,64,480 केंद्रों की मैपिंग पूरी हो चुकी है। इनमें 15,613 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे मिले हैं, जो अपने निकटतम विद्यालय से 200 मीटर के दायरे में स्थित हैं। ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय परिसर में संचालित किया जाएगा।

कोतवाली नगर पुलिस ने सर्विलेंस टीम के साथ तीन शातिर चोरों को किया गिरफ्तार

अयोध्या। कोतवाली नगर पुलिस ने सर्विलांस टीम के साथ शहर के अलग–अलग इलाकों में चोरी व लूट की वारदात करने वाले तीन शातिर चोरों को चोरी के सामान, बाइक तथा ई रिक्शा के साथ गिरफ्तार किया। गुरुवार को कोतवाली नगर परिसर में इसका खुलासा करते हुए सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी शातिर लुटेरे हैं इनके ऊपर कोतवाली नगर के साथ–साथ कोतवाली अयोध्या में भी मुकदमे दर्ज हैं।बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शिवम गौड़ उर्फ अमिष्ट गौड़ निवासी खानपुर मसौधा थाना पूराकलंदर, हिमांशू गौड़ निवासी गायत्री नगर कॉलोनी सहादतगंज थाना कैंट तथा अनुराग यादव उर्फ गोलू निवासी खोजनपुर अमौना रानीबाजार थाना पूराकलंदर के रुप मे हुए। बताया कि पिछले दिनों इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली नगर पुलिस तथा सर्विलांस के संयुक्त टीम का गठन किया गया था। जिसमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अशोक कुमार एवं पुलिस टीम ने गुरुवार सुबह करीब 4रू55 बजे जीआईसी तिराहा से जेल के पीछे मर्चरी हाउस होते हुए रेलवे स्टेशन मालगोदाम के पास से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से बाइक, ई रिक्शा, आभूषण सहित अन्य सामान बरामद किया। बताया कि इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मनोज शर्मा के अलावा सर्विलांस टीम तथा प्रभारी चौकी सिविल लाइन अशोक कुमार उप निरीक्षक पंकज सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

नालासोपारा में धूमधाम से मनाया गया कजरी महोत्सव-2026, लोक संस्कृति की छटा बिखरी

देश की उपासना समाचार पत्र
मुम्बई ब्यूरो चीफ धनन्जय विश्वकर्मा।

मुम्बई/नालासोपारा। अभियान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था एवं जय ओम सेवा संस्था के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को सेंट ल्यूक्स इंग्लिश हाई स्कूल, दुबे कंपाउंड, बिलाल पाड़ा, नालासोपारा (पूर्व) में कजरी महोत्सव–2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर लोक संस्कृति और पारंपरिक संगीत का आनंद लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ बोईसर के विधायक विलास तरे, समाजसेवी श्यामसुंदर दुबे एवं दुबे परिवार के सदस्यों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने भारतीय लोक परंपराओं के संरक्षण और सांस्कृतिक आयोजनों की आवश्यकता पर बल दिया। महोत्सव की मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध लोक गायिका संजोली पांडे रहीं। उन्होंने पारंपरिक भोजपुरी कजरी गीतों की मनमोहक प्रस्तुति देकर श्रोताओं की खूब तालियां बटोरीं। इसके अलावा उन्होंने मराठी गीत ष्मायभूमी ही, जन्मभूमी ही, कर्मभूमी अमुचीष् प्रस्तुत कर सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया। भगवान शिव की स्तुति में प्रस्तुत भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर रोलर स्केटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैलेरी लोबो को श्स्त्री शक्ति सम्मानश से सम्मानित किया गया। उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता विक्टर लोबो ने यह सम्मान कार्यक्रम के मुख्य आयोजक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता तथा महाराष्ट्र के पूर्व राज्यमंत्री अमरजीत मिश्रा के हाथों ग्रहण किया। अपने संबोधन में अमरजीत मिश्रा ने कहा कि कजरी महोत्सव जैसे आयोजन भारतीय लोक संस्कृति और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का माध्यम हैं। उन्होंने युवाओं से अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में युवा नेता अमित ओमप्रकाश दुबे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। देर शाम तक चले इस सांस्कृतिक आयोजन में लोकगीत, भक्ति संगीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का भरपूर मनोरंजन किया।

पूराकलंदर और थाना कुमारगंज क्षेत्र के दो शातिर अपराधी दुराचारी घोषित

अयोध्या। एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर के निर्देशन में जनपद पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए थाना पूराकलंदर और थाना कुमारगंज क्षेत्र के दो शातिर अपराधियों को दुराचारी घोषित कर उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर (एब्बी) प्रकार की हिस्ट्रीशीट खोली है।पुलिस के अनुसार, थाना पूराकलंदर क्षेत्र के रामलगन मौर्य (45 वर्ष) निवासी ग्राम कन्दैला के विरुद्ध विद्युत अधिनियम, मारपीट, गाली–गलौज, धमकी और बीएनएस समेत विभिन्न धाराओं में चार मुकदमे दर्ज हैं। उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें दुराचारी घोषित कर हिस्ट्रीशीट खोली गई है।वहीं थाना कुमारगंज क्षेत्र के खुशीराम पासी (30 वर्ष) निवासी ग्राम सुर्ती का पुरवा, देवगांव के विरुद्ध आयुध अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, चोरी, मारपीट सहित बीएनएस की विभिन्न धाराओं में कुल 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।वही लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के चलते पुलिस ने उन्हें भी दुराचारी घोषित करते हुए उनकी हिस्ट्रीशीट खोल दी है।अयोध्या पुलिस का कहना है कि जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ऐसे असामाजिक तत्वों की लगातार निगरानी की जा रही है। हिस्ट्रीशीट खोले जाने के बाद दोनों अपराधियों की गतिविधियों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी तथा कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

साइकिल सवार से विवाद करने पर पांच लोगों के विरुद्ध हुई कार्रवाई

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। थाना बाबा बाजार पुलिस ने एक साइकिल सवार के साथ मारपीट करने पर पांच लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की है।थानाध्यक्ष बाबा बाजार शैलेन्द्र कुमार आजाद ने बताया कि ग्राम पारा पहाड़ पुर के भंवरलाल की बाइक का पहिया मवई थाना क्षेत्र के ग्राम कोंडरा के सुभाष पुत्र गंगाराम की साइकिल में टच हो गया था।इसी बात को लेकर भंवरलाल और सुभाष के बीच कहासुनी होने लगी।इसी बीच भंवरलाल की तरफ से मदन, दद्दन पुत्र गण प्यारेलाल, धर्मेंद्र, इमरान, भंवरलाल पुत्र गण जहूरे मिलकर सुभाष के साथ विवाद करने लगे। सूचना पाकर उप निरीक्षक प्रभात कुमार द्विवेदी पुलिस कर्मियों के साथ पहुंच कर विवाद कर रहे लोगों को पकड़ कर थाने ले आये।इस संबंध मे थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार आजाद ने बताया कि मदन, दद्दन, धर्मेंद्र, इमरान, भंवर लाल को शांति भंग की धारा में चालान कर दिया गया।

विकास भवन सभागार में आयोजित मिशन शक्तिसम्मान समारोह में सीडीओ ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित

अयोध्या। मिशन शक्ति अभियान के तहत गुरुवार को विकास भवन सभागार में आयोजित मिशन शक्ति सम्मान समारोह में महिला सुरक्षा,सशक्तिकरण एवं जन जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को जिसमें खासकर सोनिया रोमी शालिनी शकुंतला तथा ईशा को प्रशस्ति–पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर महिला पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन किया।उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा इस अभियान से जुड़ी महिला पुलिसकर्मियों का योगदान सराहनीय है।इस अवसर पर महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।समारोह में महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मिशन शक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने का संकल्प भी दोहराया गया।

विगत माह शाहाबाद तहसील के बने उपजिलाधिकारी डॉ अवनीश कुमार से पत्रकारों ने की शिष्टाचार भेंट'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली(हरदोई)' गुरुवार को शाहाबाद तहसील के वरिष्ठ उपजिलाधिकारी डॉ अवनीश कुमार से कई पत्रकारों सहित शाहाबाद के प्रतिष्ठित समाजसेवी प्रवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पत्रकारों और एसडीएम के बीच क्षेत्र से संबंधित कई विषयों पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान एसडीएम डॉ अवनीश कुमार ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुरूप कार्य करना तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करना,पीड़ितों को न्याय दिलाना उनकी सर्वोत्तम प्राथमिकता होगी,साथ ही शाहाबाद तहसील क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी से गुजरना नहीं पड़ेगा। तहसील में मेरे पास आने वाली प्रत्येक जन शिकायत का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जायेगा, उन्होंने कहा कि हर संभव प्रयास रहेगा कि कोई भी फरियादी

तहसील से निराश होकर न जाये। खनन के मामले में उन्होंने कहा कि खनन से संबंधित शिकायत मिलने पर जांच कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि जनहितध्प्रशासनिक कार्य हित में जनपद में कार्यरत डिप्टी कलेक्टर एसडीएम डॉ अवनीश कुमार को विगत माह में शाहाबाद तहसील का कार्यभार सौंपा गया। उन्होंने निवर्तमान एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। सुशील कुमार मिश्रा का तबादला जनपद बरेली की तहसील आंवला में होने के पश्चात एसडीएम डॉ अवनीश कुमार ने विगत माह पदभार ग्रहण किया था। एसडीएम डॉ अवनीश कुमार 2015 बैच के एक कुशल,अनुभवी,न्याय प्रिय प्रशासनिक अधिकारी है। जानकारी के मुताबिक जनपद बहराइच के आप मूल निवासी हैं। एसडीएम डॉ अवनीश कुमार इससे पूर्व जनपद खीरी की तहसील पलिया, तहसील मोहम्मदी आदि तहसीलों में सेवा दे चुके हैं।

गैर मान्यता प्राप्त संचालित अनमोल पब्लिक स्कूल को शिक्षा विभाग जारी किया नोटिस

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। जिले के रुदौली शिक्षा क्षेत्र में नियम–कायदों को दरकिनार कर अवैध रूप से चलाए जा रहे निजी विद्यालयों पर शिक्षा विभाग की मेहरबानी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है।खण्ड पिपरा स्थित अनमोल पब्लिक स्कूलश बिना किसी मान्यता और मानक विहीन व्यवस्थाओं के धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है।बिना मान्यता के स्कूल चलने का यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है,जबकि जिम्मेदार अधिकारी अब तक खामोशी साधे हुए थे।सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल प्रबंधन ने केवल कक्षा 6 से 8 तक की मान्यता का दावा किया है, जबकि इसकी आड़ में अन्य गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं भी बेधड़क चलाई जा रही हैं। मानकों को दरकिनार कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।इस मामले में जब खंड शिक्षा अधिकारी राम कांत राम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। स्कूल के पास वैध मान्यता नहीं है।उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष ही इस स्कूल को बंद करने के कड़े निर्देश दिए गए थे और नोटिस भी जारी की गई थी। खंड शिक्षा अधिकारी रमा कांत राम ने बताया कि अनमोल पब्लिक स्कूल खण्डपिपरा को विद्यालय बंद करने की नोटिस जारी किया गया।इस अनधिकृत स्कूल को अतिशीघ्र बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी।अब देखने वाली बात यह होगी कि विभाग केवल कागजी नोटिस तक सीमित रहता है।धरातल पर इस गैर–मान्यता प्राप्त स्कूल पर कोई ठोस कार्रवाई करता है।

आरसीसी नाले के निर्माण में लापवाही पर ठेकेदार पर एक लाख का अर्थदंड

गोरखपुर, (संवाददाता)। वार्ड संख्या 56 रघुपति सहाय फिराक नगर में निर्माण कार्यों में अनियमितता और धीमी प्रगति का मामला उठाने के बाद नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नाला निर्माण में लापरवाही पर दोबारा निर्माण तोड़कर कार्य करने को कहा गया है। इसी वार्ड में दूसरी जगह पर निर्माण में धीमी प्रगति पर ठेकेदार पर एक लाख का अर्थदंड लगा है। सोमवार को उपसभापति पूनम सिंह ने स्थानीय पार्षद रविंद्र सिंह के साथ 3.37 करोड़ रुपये की लागत से चल रही दो निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण किया था। उपसभापति के निरीक्षण के बाद जांच में इंद्रानगर में रणविजय सिंह के मकान से ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव, बाबा सेटर स्कूल, उदय प्रताप, सजल पेंट हाउस, बाइखंड ऑफिस व विभिन्न गलियों में 1.64 करोड़ रुपये की लागत से बन रही आरसीसी नाली एवं सीसी सड़क परियोजना में कार्य की गुणवत्ता और प्रगति संतोषजनक नहीं मिली। इसी तरह संजय किराना से अनिल किराना, उर्मिला हॉस्पिटल, विनय सिंह, मल्ल महासभा, रामनिवास यादव से सावित्री स्कूल तक तथा आसपास की गलियों में 1.72 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे आरसीसी नाली एवं सीसी सड़क निर्माण कार्य में भी अधोमानक निर्माण और धीमी प्रगति सामने आई। अधिशासी अभियंता अशोक भाटी ने ठेकेदार को अधोमानक निर्माण कार्य तोड़कर मानक के अनुरूप दोबारा कराने, श्रमिकों की संख्या बढ़ाने और निर्माण कार्य में तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में सुधार नहीं हुआ तो शंभवी डेवलपर्स को ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति की जाएगी। इसी वार्ड में उपसभापति ने निरीक्षण में सीवरेज एवं जल निकासी योजना के तहत चल रहे कार्य पर सवाल खड़े किए गए थे। जांच में ट्रांसफार्मर से मल्ल महासभा तक करीब 2.30 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे आरसीसी नाले के निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षा से काफी धीमी मिली। इस पर नगर निगम ने निर्माण एजेंसी मेसर्स नव दुर्गा कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर दिसंबर तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

एआई से मुख्यमंत्री की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर डालने वाला युवक गिरफ्तार

गोरखपुर, (संवाददाता)। कैंपियरगंज पुलिस ने एआई की मदद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की और पोस्ट करने वाले युवक तक पहुंच बनाई। इसके बाद मंगलवार को कहरौली निवासी करन को गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही है।

गोरखपुर पहुंचीं राज्यपाल, कुलपति ने किया अभिनंदन

गोरखपुर, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मंगलवार की देर शाम सड़क मार्ग से गोरखपुर पहुंचीं। वह यहां गोरखपुर विश्वविद्यालय के

अतिथि गृह में ठहरी हैं। कुलाधिपति छह को लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगी। कुलाधिपति पांच को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और छह अगस्त को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगी। मंगलवार शाम विश्वविद्यालय पहुंचने पर कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस मौके पर एमएमएमयूटी की कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा, अतिथि गृह के प्रभारी डॉ. दीपेंद्र मोहन सिंह आदि मौजूद रहे।

गोवंश सुपुर्दगी अभियान का उठाये लाभ पशुपालक

अयोध्या। मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने जनपद अयोध्या के सभी पशुपालक को सूचित किया जाता है कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ गोवंश सहभागिता योजनान्तर्गत स्थानीय स्थायीध्अस्थायी गोआश्रय स्थलों से गोवंश सुपुर्दगी का अभियान चलाया जा रहा है।जिसमें इच्छुक पशुपालक जो सम्बन्धित विकास खण्ड के मूल निवासी हों तथा वर्तमान में निवास कर रहे हों, वे अधिकतम चार गोवंश प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें नववत्सों की गणना नहीं की जाएगी। प्रति पशु प्रतिदिन रू0 50ध्– (पचास रू० मात्र) की दर से शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप धनराशि, जो सीधे बैंक खातों में देय होगी।सभी पशुपालकों से अपील की जाती है कि वे अपने नजदीकी गोवंश आश्रय स्थलों से सुपुर्दगी में निराश्रित गोवंश प्राप्त कर योजना का लाभ उठायें।

जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर डीएम सख्त

गोरखपुर, (संवाददाता)। पिछले दिनों एक बच्ची के अपहरण और हत्या की घटना के बाद जिला अस्पताल की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को परखने के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। डीएम ने इस दौरान आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएमओ कार्यालय के पास बेकार सामान पड़े मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई और उसके तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। दवा भंडारण व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए उन्होंने सभी अलमारियों पर दवाओं का स्पष्ट विवरण अंकित करने, स्टॉक और वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित करने और मरीजों को बिना भटके दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बायोमीट्रिक उपस्थिति की भी जांच की गई। डीएम ने डायलिसिस यूनिट का निरीक्षण किया।

तेज रफ्तार ट्रक ने दो वर्षीय बच्ची को कुचला, तीन घंटे तक सड़क जाम

गोरखपुर, (संवाददाता)। बेलीपार थाना क्षेत्र के कसिहार–मलाव मार्ग पर मंगलवार शाम तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो वर्षीय बच्ची सृष्टि की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची का शव सड़क पर रखकर करीब तीन घंटे तक कसिहार–मलाव मार्ग जाम रखा।

एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया। जानकारी के अनुसार, मलांव गांव के चौराहे पर शाम करीब छह बजे बालू खाली कर चंदा घाट की ओर से लौट रहा खाली ट्रक घर के सामने खेल रही सृष्टि पुत्री गौतम मौर्य को कुचलते हुए निकल गया। हादसे में बच्ची की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर भागने की कोशिश करने लगा लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर कुछ दूरी पर उसे वाहन समेत पकड़ लिया।

घटना से नाराज ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान मुकुंद नारायण सेवक पांडेय के नेतृत्व में शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और कसिहार–मलाव मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। सूचना पर बेलीपार पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। बाद में एसडीएम बांसगांव मलखान सिंह और सीओ अनुज कुमार सिंह ने ग्रामीणों से वार्ता की। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। एसडीएम ने पोस्टमार्टम से पहले मार्ग पर बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए बैरियर लगाने और अन्य मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद रात करीब नौ बजे ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया।

शंकराचार्य विवाद से चर्चा में थी, डॉ. लोकेश एम. नए कमिश्नर

प्रयागराज, (संवाददाता)। प्रयागराज मंडल में मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन ने 13 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके तहत प्रयागराज की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल का तबादला कर उन्हें श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी जगह डॉ. लोकेश एम. को प्रयागराज का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। सौम्या अग्रवाल ने सितंबर 2025 में प्रयागराज मंडलायुक्त का पद संभाला था। वह प्रयागराज मंडल की पहली महिला मंडलायुक्त बनी थीं। 2008 बैच की आईएएस अधिकारी सौम्या अग्रवाल उत्तर प्रदेश कैडर की अधिकारी हैं। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी में बीटेक की पढ़ाई की है।

सड़कों के फुटपाथ व नालियों पर अतिक्रमण, पैदल चलने वालों को परेशानी

गोरखपुर, (संवाददाता)। शहर की सड़कों पर नगर निगम व पुलिस प्रशासन की ओर से अतिक्रमण अभियान हमेशा चलाया जाता है। फुटपाथ से भी अतिक्रमण हटवाया जाता है लेकिन इसके बाद भी दोबारा अतिक्रमण हावी हो जाता है। इससे सड़कों के किनारों पर चलना मुश्किल हो जाता है। मंगलवार को भी विभिन्न सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अतिक्रमण देखा गया। गोलघर में कचहरी चौक से लेकर गणेश चौक तक बाईं ओर बने नाले व पैदल चलने वाले रास्ते पर व्यापारियों की ओर से अतिक्रमण किया गया था। दुकानों के सामानों को बाहर की तरफ बढ़ा कर रखा गया था, जिससे दुकान के सामने से आने–जाने में परेशानी रही। इसके साथ ही आगे रेलवे स्टेशन रोड पर सड़क की चौड़ाई भीड़ की तुलना में पहले ही कम है, उसमें भी कई दुकानों के सामने स्लैब पर सामान रखे हुए थे। रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन रोड पर दोनों ओर नालों पर बने फुटपाथ पर दुकानदारों का कब्जा रहा। इससे जाम की स्थिति भी बनी रही। इसके आगे भी देखा गया कि नाले की स्लैब पर जहां लोग पैदल चलते हैं, दुकानें सजी रहीं। वहीं, गोलघर के काली मंदिर से पुलिस लाइन जाने वाली सड़क पर शुरू में ही एक चाय की दुकान है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।